

अध्याय

3

एफ आर बी एम लक्ष्य
और उपलब्धियां

3.1 एफ आर बी एम लक्ष्य

एफ आर बी एम अधिनियम 2003 और एफ आर बी एम नियम 2004, समय-समय पर संशोधित, नवीनतम अप्रैल 2018 में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में प्राप्त किए जाने वाले वित्तीय संकेतकों के लिए लक्ष्य और मानदंड प्रदान करते हैं, जैसा कि इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1 और 2** में चर्चा की गई है। संक्षेप में पुनर्गणना करने के लिए, लक्ष्य/बेंचमार्क इस प्रकार थे:

- क. 2018-19 से सकल घरेलू उत्पाद के 0.10 प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर राजकोषीय घाटे (एफ डी) की वार्षिक कमी और वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करना अनिवार्य है।
- ख. समय-समय पर संशोधित एफ आर बी एम नियम 7, बी ई के कम से कम 40 प्रतिशत की गैर-ऋण प्राप्तियों के संग्रह के लिए मध्य-वर्ष (अर्थात्, सितंबर के अंत), और वर्ष के लिये आर डी और एफ डी के लिए अधिकतम 70 प्रतिशत मानदंड निर्धारित करता है। यदि ये मानदंड भंग हो जाते हैं, तो संसद में एक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का विवरण होता है।

वित्तीय संकेतकों के लिए उपर्युक्त लक्ष्यों के संबंध में उपलब्धि की स्थिति और सीमा, और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मध्य-वर्ष के बेंचमार्क की चर्चा इस अध्याय के बाद के पैराआकृति में की गई है।

28 फरवरी 2022 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) द्वारा जारी आधार वर्ष 2011-12 के साथ मौजूदा मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए के लिए जी डी पी के दूसरे संशोधित अनुमान को विश्लेषण के लिए अपनाया गया है।

3.2 घाटे के आंकड़ों और सार्वजनिक ऋण का स्नैपशॉट

एम ओ एस पी आई प्रैस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जी डी पी वर्तमान मूल्य पर ₹2,00,74,856 करोड़ थी (28 फरवरी, 2022)। हालांकि, अधिनियम ने एफ डी के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं, पी डी के लिए लक्ष्य नहीं निर्धारित किये गये थे। 2018 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रभावी आर डी लक्ष्यों को समाप्त कर दिया है और एम टी एफ पी विवरणी में राजकोषीय संकेतक के रूप में प्राथमिक घाटा दर्शाने के लिये एफ आर बी एम नियमों को अनिवार्य कर दिये ।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में जब एफ आर बी एम अधिनियम लागू हुआ था, की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा व सार्वजनिक ऋण के राजकोषीय पैरामीटर तथा जी डी पी बढ़ गया था। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 (जी डी पी का 4.25 प्रतिशत) में गिरावट के बाद से वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2018-19 (वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3.49 प्रतिशत जी डी पी की रेंज से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4.15 प्रतिशत जी डी पी) में राजकोषीय घाटा स्थिर रहा, यद्यपि वित्तीय वर्ष 2019-20 यह बढ़ गया (बी ए जी के अनुसार 4.65 प्रतिशत⁹ जी डी पी तथा यू जी एफ ए के अनुसार 5.14 प्रतिशत जी डी पी) ऊपर चला गया।

एफ डी से ब्याज भुगतान घटाने पर पी डी प्राप्त होता है। इस प्रकार, यह उधार की राशि को मापता है जिसका उपयोग सरकार द्वारा ब्याज भुगतान के अलावा अन्य के लिए किया जा सकता है। पी डी में कमी राजकोषीय स्वास्थ्य की दिशा में प्रगति दर्शाती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, वित्तीय वर्ष 2016-17 में सबसे कम पी डी ₹33,861.67 करोड़ रहा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.22 प्रतिशत था। इसके बाद, पी डी वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.87 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1.00 प्रतिशत की महत्वपूर्ण छलांग के साथ ऊपर की ओर था।

3.3 राजस्व घाटा

3.3.1 मध्य-वर्ष के बेंचमार्क का अनुपालन

एफ आर बी एम नियम, 2004 का नियम 2(सी ए) राजस्व घाटा (आर डी) को किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित करता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आर डी के संबंध में मध्य-वर्ष के मानदंड के अनुपालन की स्थिति आकृति 3.1 में दी गई है।

आकृति 3.1: राजस्व घाटे के लिए निर्धारित मध्य-वर्ष के बेंचमार्क का अनुपालन

	एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक	विचलन
मध्य वर्ष मानदंड (30 सितंबर 2019) (बी ई के प्रतिशत के अनुसार)	बी ई के 70% से अधिक नहीं	99.8%	29.8%

स्रोत: 2019-20 के लिए मध्य-वर्ष बेंचमार्क के प्रति वास्तविक के लिए मध्य-वर्ष का विवरण

⁹ बी ए जी (जी डी पी का 4.65%) और यू जी एफ ए (जी डी पी का 5.14%) में राजकोषीय घाटे का अंतर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (₹65,443 करोड़), राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता (₹20,607 करोड़) के लिए पूंजी प्रवाह पर कुछ खर्चों को छोड़कर है, और अन्य खर्च ₹11,425 करोड़ है।

आकृति 3.1 से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आर डी के लिए निर्धारित मध्य वर्ष के बेंचमार्क से विचलन था। पूरे वर्ष के लिए बी ई के 70 प्रतिशत पर आर डी रखने के लक्ष्य के मुकाबले, आर डी मध्य वर्ष के बिंदु पर यानी सितंबर 2019 के अंत में बी ई का 99.8 प्रतिशत था।

एफ आर बी एम नियमों के नियम 7 के तहत संसद में पेश किए जाने के लिए आवश्यक बयान में, जब मानदंड लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था, वित्त मंत्रालय ने विचलन को 'कम कर राजस्व' के साथ-साथ 'पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय की उच्च गति' के लिए जिम्मेदार ठहराया। बयान में निधि को न्यूनतम रखना, 'अनुदान के लिए की अनुपूरक मांग की स्थिति में उनकी मांगों के भीतर पहचानी गई बचत से धन के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति' और 'कर प्राप्तियों सहित गैर-ऋण प्राप्तियों के लिए लक्ष्यों की उपलब्धि सुधारात्मक उपायों को सुनिश्चित करने के प्रयास' को सूचीबद्ध किया गया है।

3.3.2 राजस्व और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

आकृति 3.2 कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

आकृति 3.2: राजस्व और पूंजीगत व्यय का रुझान विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल खर्च	कुल व्यय के प्रतिशत के अनुसार राजस्व व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत व्यय
2015-16	17,79,529	2,78,866	21,05,667	84.51%	13.24%
2016-17	19,33,018	2,49,472	22,42,501	86.20%	11.12%
2017-18	21,40,085	3,25,116	25,47,337	84.01%	12.76%
2018-19	22,61,571	3,99,523	27,15,761	83.28%	14.71%
2019-20	26,15,320	3,87,744	30,48,206	85.80%	12.72%

स्रोत: संबंधित वर्षों का यू जी एफ ए

आकृति 3.2 से देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में, जबकि कुल व्यय के अनुपात के रूप में राजस्व व्यय में 2019-20 के दौरान वृद्धि हुई, पूंजीगत व्यय में कुल व्यय के अनुपात के साथ-साथ दोनों में कमी आई।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक के साथ पूंजीगत व्यय के अनुमानों की तुलना में, यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एम टी ई एफ में प्रारंभिक प्रक्षेपण ₹3,90,000 करोड़ के लिए था, जिसे संशोधित करके वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एम टी ई एफ में ₹3,27,197 करोड़ और ₹3,38,569 करोड़ का बजट था और वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹3,48,907 करोड़ का संशोधन किया। ₹3,87,744 करोड़ का वास्तविक पूंजीगत व्यय हालांकि बजटीय अनुमानों से अधिक था लेकिन प्रारंभिक अनुमान से थोड़ा कम था।

3.4 राजकोषीय घाटा

एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 2(ए) एफ डी को परिभाषित करती है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सी एफ आई से कुल संवितरण की अधिकता, ऋण प्राप्तियों और ऋण चुकौती को छोड़कर, निधि में कुल प्राप्तियों से अधिक है।

3.4.1 राजकोषीय घाटे का लक्ष्य

ज्ञात हो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अप्रैल 2018 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के एफ डी लक्ष्य को प्राप्त किया जाना था, और वार्षिक कमी लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 0.10 प्रतिशत तय किया गया था। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 तक तीन प्रतिशत के एफ डी लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके के प्रति वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.30 प्रतिशत के एफ डी लक्ष्य में बताया गया है।

एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार, राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष में सी एफ आई में गैर-ऋण प्राप्तियों पर सी एफ आई से कुल संवितरण (ऋण चुकौती को छोड़कर) की अधिकता है।

आकृति 3.3: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे की गणना

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	राशि (यूजीएफए के अनुसार)
1.	गैर-ऋण प्राप्तियां	20,17,080
	राजस्व प्राप्तियां	19,48,084
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	50,349
	ऋण और अग्रिम की वसूली	18,647
2	कुल संवितरण (ऋण चुकौती को छोड़कर)	30,48,205
	राजस्व व्यय	26,15,320
	पूंजीगत व्यय	3,87,744
	ऋण और अग्रिम	45,142

3.	यू जी एफ ए के अनुसार राजकोषीय घाटा (2-1),	10,31,126
4.	यू जी एफ ए के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में एफ डी	5.14%
5.	बी ए जी के अनुसार, राजकोषीय घाटा	9,33,651
6.	बी ए जी के अनुसार, एफ डी सकल घरेलू उत्पाद के % के रूप में	4.65%

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट दस्तावेज और यू जी एफ ए

राजकोषीय घाटे में ₹97,475 करोड़ की अंतर राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी प्रवाह पर कुल व्यय के कारण बी ए जी (सकल घरेलू उत्पाद का 4.65%) तथा यू जी एफ ए (सकल घरेलू उत्पाद का 5.14%) में दर्शाई गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए यू जी एफ ए के विवरण 11 और बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 में भी, राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता (₹20,607 करोड़) जहां केंद्र राज्यों के लिये ऋणों के संवितरण के लिए केवल माध्यम एक एजेंसी है और अन्य व्यय की ₹11,425 करोड़ की राशि को प्राप्तियों के साथ निवल किया गया था।

3.4.2 बजट अनुमान के साथ मध्य-वर्ष के मानदंड का अनुपालन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एफ डी के संबंध में मध्य-वर्ष के बेंचमार्क के अनुपालन की स्थिति आकृति 3.4 में दी गई है।

आकृति 3.4: राजकोषीय घाटे के लिए निर्धारित मध्य-वर्ष के बेंचमार्क का अनुपालन

	एफ आर बी एम अधिनियम के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक	विचलन
मध्य वर्ष बेंचमार्क (30 सितंबर 2019) (बी ई के प्रतिशत के अनुसार)	बी ई के 70% से अधिक नहीं	92.6	22.6

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मध्य-वर्ष बेंचमार्क के प्रति वास्तविक के लिए मध्य-वर्ष का विवरण।

30 सितंबर 2019 तक राजकोषीय घाटा (एफ डी) को पूरे वर्ष के बजट अनुमान के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं रखने के मध्य-वर्ष के बेंचमार्क के विपरीत, वास्तविक राजकोषीय घाटा मध्य वर्ष तक बजट अनुमान के 92.60 प्रतिशत तक पहुंच गया।

3.4.3 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटा-अनुमान और वास्तविक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफ डी के लिए एफ आर बी एम लक्ष्यों के प्रति बी ई, आर ई और वास्तविक का विवरण आकृति 3.5 में दिया गया है।

आकृति 3.5: वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा-अनुमान और वास्तविक

(₹ करोड़ में)

घटक	कुल खर्च	गैर-ऋण प्राप्ति	राजकोषीय घाटा (एफडी)	सकल घरेलू उत्पाद
बजट अनुमान	27,34,428	24,19,241	3,15,187	2,10,07,439
संशोधित अनुमान	27,42,684	22,72,751	4,69,933	2,04,42,233
वास्तविक	30,48,206	20,17,080	10,31,126	2,00,74,856
बजट अनुमानों से वास्तविक की भिन्नता	3,13,778	-4,02,161	7,15,939	
संशोधित अनुमानों से वास्तविक की भिन्नता	3,05,522	-2,55,671	5,61,193	

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सार, बी ई और आर ई के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 का ए एफ एस, वास्तविक के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का यू जी एफ ए, और वास्तविक जी डी पी आंकड़े नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं।

बी ई से एफ डी के संबंध में पर्याप्त अंतर गैर-ऋण प्राप्ति संग्रह अनुमानों से काफी कम होने के कारण था। सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बी ए जी¹⁰ और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए यू जी एफ ए के अनुसार कुल व्यय के बीच के अंतर का भी समाधान कर सकती है। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफ आर बी एम लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.30 प्रतिशत था, वर्ष के लिए बी ई ने 1.5 प्रतिशत से कम स्तर पर यही अनुमान लगाया। इसके बाद, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 2.30 प्रतिशत हो गया। इस ऊर्ध्वगामी संशोधन को कम गैर-ऋण प्राप्ति के साथ-साथ संशोधित अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

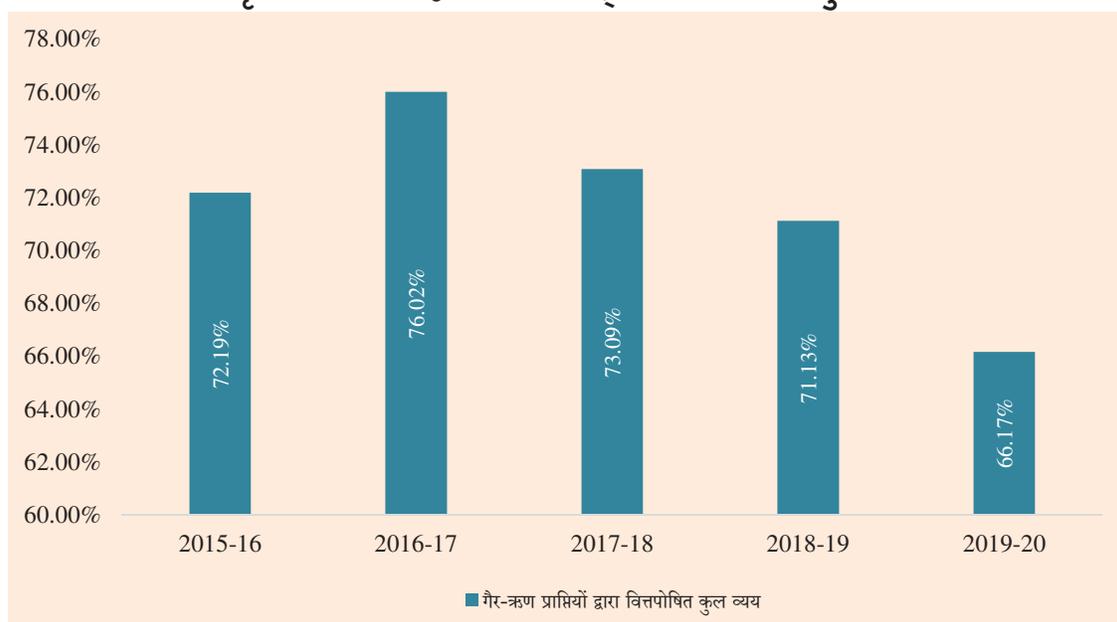
मंत्रालय ने भिन्नता को (फरवरी 2022) सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्निहित हास के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि भिन्नताओं को न्यूनतम स्तर पर रखने के प्रयास किए जा रहे थे।

3.4.4 गैर-ऋण प्राप्ति के माध्यम से कुल व्यय का कवरेज

आकृति 3.6 पिछले पांच वर्षों में गैर-ऋण प्राप्ति द्वारा कवर किए गए कुल व्यय के अनुपात को दर्शाता है। विवरण अनुलग्नक 3.1, 3.2 और 3.3 में संदर्भित किया जा सकता है।

¹⁰ बी ए जी 2022 के अनुसार, कुल व्यय, गैर-ऋण प्राप्ति और राजकोषीय घाटा के लिए वास्तविक क्रमशः ₹26,86,330 करोड़, ₹17,52,679 करोड़, और ₹9,33,651 करोड़ थे। बी ई और आर ई आंकड़ों से वास्तविक की भिन्नता का विश्लेषण करने के लिए, ए एफ एस में उपलब्ध शीर्ष-वार ब्रेकअप का उपयोग किया गया है।

आकृति 3.6: गैर-ऋण प्राप्तियों द्वारा वित्तपोषित कुल व्यय



स्रोत: संबंधित वर्षों का यू जी एफ ए। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जी डी पी के आंकड़े अपडेट किए गए हैं।

पिछले चार वित्तीय वर्षों 2015-16 से 2018-19 के लिए, गैर-ऋण प्राप्तियों ने कुल व्यय को 76.02 प्रतिशत से 71.13 प्रतिशत की सीमा में वित्तपोषित किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में, गैर-ऋण प्राप्तियां कुल व्यय का 66.17 प्रतिशत का वित्तपोषण करने में सक्षम थीं।

3.5 राजकोषीय नीति विवरणी में वास्तविक की तुलना में किए गए अनुमान

एफ आर बी एम अधिनियम के बताये गये उद्देश्यों में से एक यह है कि केंद्र सरकार मध्यम अवधि के ढांचे में अपने राजकोषीय नीति का संचालन करेगी। इसे प्राप्त करने के लिए, अधिनियम की धारा 3 में सरकार को वार्षिक वित्तीय विवरण (ए एफ एस) अनुदान की मांग से साथ संसद के प्रचालन दोनों सदनों में राजकोषीय नीति विवरण, अर्थात् मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) वक्तव्य, राजकोषीय नीति रणनीति (एफ पी एस) विवरण और मैक्रो-आर्थिक ढांचा (ए म एफ) विवरण रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, 2012 में एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन के द्वारा, एक मध्यम अवधि के व्यय ढांचे (एम टी ई एफ) विवरण को भी संसद में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

अप्रैल 2018 में एफ आर बी एम अधिनियम के संशोधन के बाद, अलग-अलग विवरणों के बजाय एक एकल मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति (एम टी एफ पी सह एफ पी एस) विवरण पेश किया गया था। मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (एम ई एफ) और माध्यम अवधि व्यय-टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क (एम टी ई एफ) विवरण को पहले की तरह संसद में रखा जाना था। नियम यह भी प्रदान करते हैं कि एम टी एफ पी सह एफ पी एस में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार एफ डी, आर डी, प्राथमिक घाटा, कर राजस्व,

गैर-कर राजस्व और केंद्र सरकार के ऋण के लिए तीन वर्ष के रोलिंग लक्ष्य शामिल होंगे। एम टी एफ पी सह एफ पी एस विवरण में राजकोषीय दृष्टिकोण, सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमानों और प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों के बारे में विस्तार से अनुमान लगाने की भी आवश्यकता थी। एम टी ई एफ विवरण सभी निर्धारित व्यय संकेतकों के लिए अंतर्निहित मान्यताओं और शामिल जोखिमों के विवरण के साथ तीन साल का रोलिंग लक्ष्य प्रदान करता है।

निम्नलिखित आकृति 3.7 में वित्तीय नीति विवरणों और बजट दस्तावेजों में निहित अनुमानों/अनुमानों के प्रति वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय के बीच अंतर का विश्लेषण शामिल है।

आकृति 3.7: बजट में किए गए अनुमानों/अनुमानों के प्रति वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	प्राप्तियां	एम टी एफ पी 2017-18	एम टी एफ पी 2018-19	बी ई 2019-20	आर ई 2019-20	वास्तविक 2019-20
(1)	कर राजस्व	16,27,275	16,74,523	16,49,582	15,04,587	13,59,382
(2)	गैर -कर राजस्व	2,74,735	2,72,110	3,13,179	3,45,514	3,27,157
(3)	राजस्व प्राप्तियां	19,02,010	19,46,633	19,62,761	18,50,101	16,86,539
	जिसकी पूंजीगत प्राप्तियां:					
(4)	(i) ऋणों और अग्रिमों की वसूली	10,000	10,000	14,828	16,605	18,647
(5)	(ii) अन्य गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	40,000	60,000	1,05,000	65,000	50,349
(6) = (3+4+5)	गैर-ऋण प्राप्तियां	19,52,010	20,16,633	20,82,589	19,31,706	20,17,080
(7) = (10 -6)	(iii) उधार-सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियां	6,43,763	6,25,588	7,03,760	7,66,846	10,31,125

	व्यय	एम टी ई एफ 2017-18	एम टी ई एफ 2018-19	बी ई 2019-20	आर ई 2019-20	वास्तविक 2019-20
(8)	व्यय (सी)	22,05,772	23,15,024	24,47,780	23,49,645	26,15,320
(9)	पूँजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सहित)	3,90,000	3,27,197	3,38,569	3,48,907	4,32,886
(10)	कुल व्यय	25,95,773	26,42,221	27,86,349	26,98,552	30,48,206
(11) = (6 -10)	राजकोषीय घाटा	-6,43,763	-6,25,588	-7,03,760	-7,66,846	-10,31,125 (यू जी एफ ए) -9,33,651 (बी ए जी)
(12)	सकल घरेलू उत्पाद	2,11,33,448	2,09,31,533	2,10,07,439	2,04,42,233	2,00,74,856

स्रोत: वास्तविक के लिए बी ई, आर ई और यू जी एफ ए के लिए बी ए जी (गैर-कर राजस्व को छोड़कर, जो बी ए जी से लिया गया है), और सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक आंकड़ों को नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अद्यतन किया गया है। घाटे के आंकड़े नकारात्मक संकेत के साथ दिखाए गए हैं।

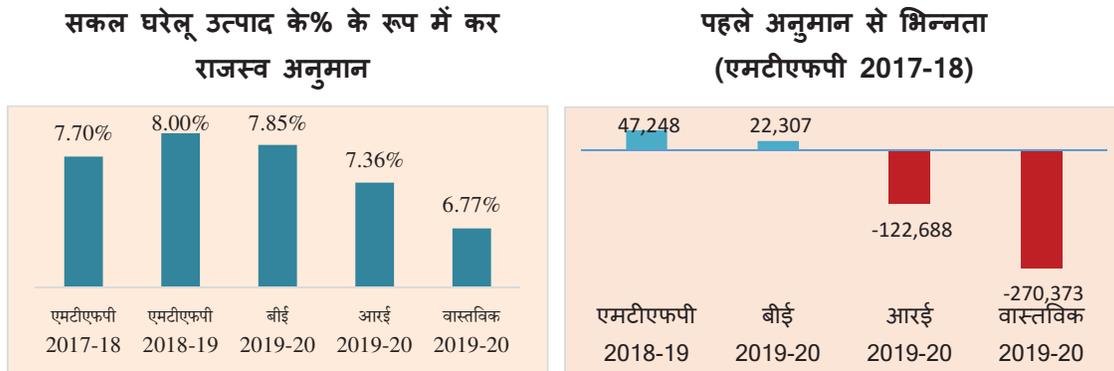
3.5.1 कर और गैर-कर राजस्व के लिये अनुमान

प्रत्येक वर्ष के एम टी एफ पी विवरण सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व और गैर-कर राजस्व¹¹ का अनुमान देते हैं। इन अनुमानों की तुलना वास्तविक और इस खंड में विश्लेषण की गई विविधताओं से की गई है।

¹¹ एनटीआर प्राप्तियों में आरबीआई, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश, मुख्य रूप से राज्यों से ऋण पर ब्याज प्राप्तियां शामिल हैं। अन्य एनटीआर प्राप्तियों में दूरसंचार प्राप्तियां, अपतटीय तेल क्षेत्रों से प्राप्तियां, उपयोगकर्ता प्रभार और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगाए गए शुल्क शामिल हैं।

आकृति 3.8: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर राजस्व अनुमान
(विवरण के लिए अनुलग्नक 3.4 देखें)

(₹ करोड़ में)

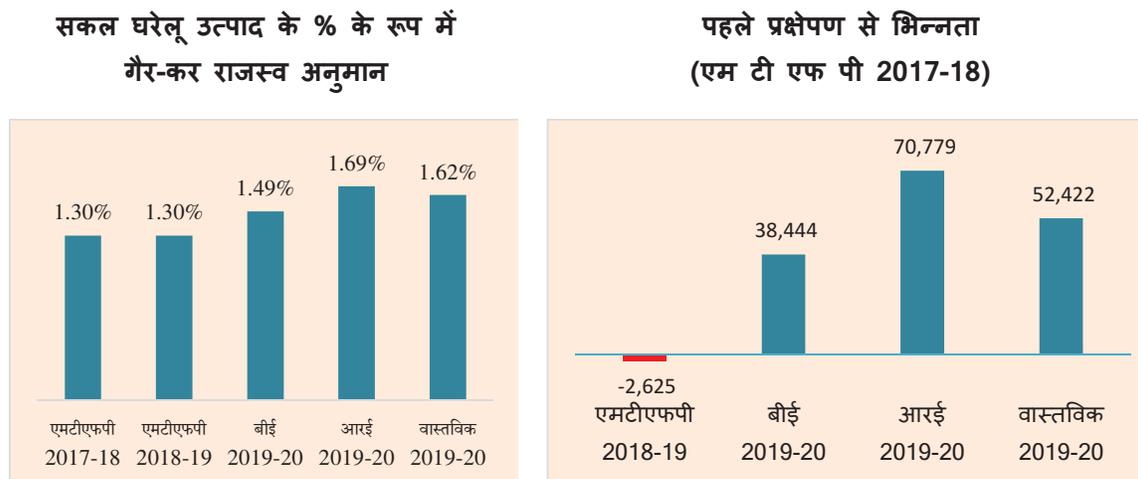


इस प्रकार, अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों में कमी थी। यह निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम ए टी), आदि में कटौती के कारण था।

संकेतकों के अनुमानों के साथ, कर राजस्व के अनुमानों में भी लगातार संशोधन और अंत में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।

आकृति 3.9: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गैर-कर राजस्व अनुमान
(विवरण के लिए अनुलग्नक 3.5 देखें)

(₹ करोड़ में)



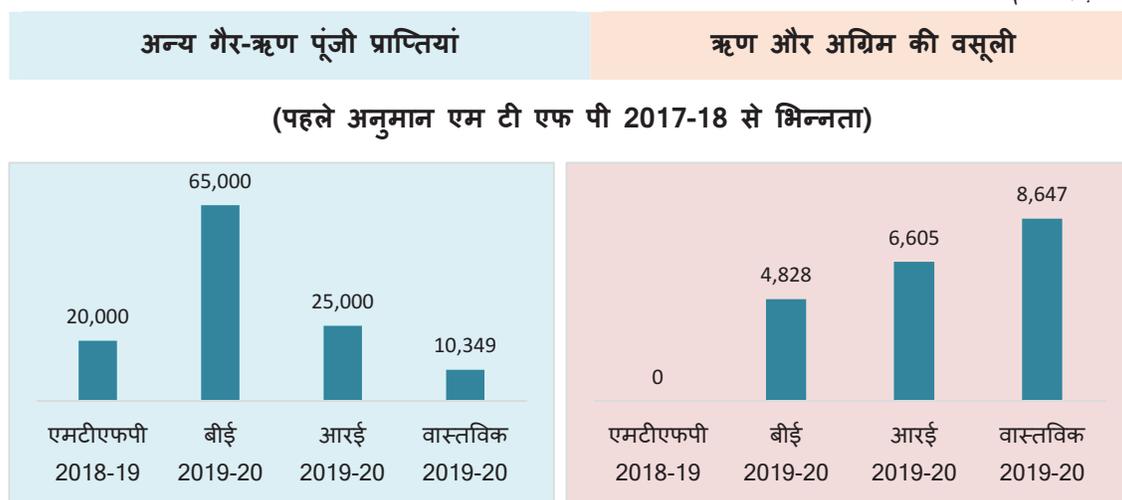
कर राजस्व अनुमानों के प्रति, गैर-कर राजस्व अनुमानों को भी ऊपर की ओर संशोधित किया गया था। आर ई को छोड़कर, वास्तविक गैर-कर राजस्व संग्रह अनुमानों की तुलना में काफी अधिक था।

3.5.2 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के लिए अनुमान

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 'ऋण और अग्रिमों की वसूली' और 'अन्य गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां' शामिल हैं जो मुख्य रूप से विनिवेश प्राप्तियां¹² हैं।

आकृति 3.10: वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का अनुमान
(विवरण के लिए अनुलग्नक 3.6 और 3.7 देखें)

(₹ करोड़ में)



'ऋणों और अग्रिमों की वसूली' के अनुमानों में लगातार वृद्धि की गई, और वास्तविक आर ई से 12 प्रतिशत अधिक¹³ थे। दूसरी ओर, 'अन्य गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों' के मामले में, आर ई चरण में अनुमान काफी कम था, जबकि वास्तविक बी ई की तुलना में 52.05 प्रतिशत और आर ई की तुलना में 22.54 प्रतिशत कम थे।

बी ई/आर ई से अंतर इसलिए था क्योंकि योजना के अनुसार सी पी एस ई का विनिवेश अमल में नहीं लाया जा सका।

3.5.3 एफडी के वास्तविक अनुमानों की तुलना में अनुमानों का विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एम टी एफ पी में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एफ डी हेतु अनुमान तीन प्रतिशत पर रखा गया था, जो कि विकास पुनरुद्धार की उम्मीदों के आधार पर और वित्तीय वर्ष 2018-19 के मामले में व्यय और कर सुधारों पर आधारित था। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एम टी एफ पी ने एफ डी में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु बी ई ने एफ डी में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसे 'राजकोषीय शुद्धता के पथ पर' वापसी के रूप में देखा गया। यह उच्च प्राप्तियों और व्यय

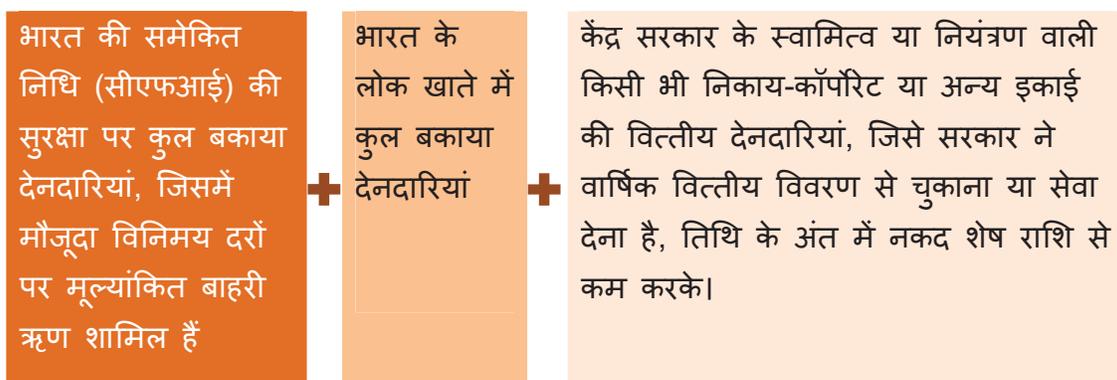
¹² व्यक्तिगत लेनदेन से विनिवेश प्राप्तियों का डेटा डी आई पी ए एम वेबसाइट से लिया गया है।

¹³ बी ए जी वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक ₹18,316 करोड़ था, जिसमें आर ई के आंकड़े से भिन्नता 10.30 प्रतिशत होगी।

के युक्तिकरण की अपेक्षाओं पर आधारित था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये आई में, एफ डी का अनुमान बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया था। यह बताते हुए कि यह 31 मार्च 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के आस्थगित लक्ष्य की ओर एफ डी की क्रमिक कमी को दर्शाता है और यह एफ आर बी एम नियम 2004 के नियम 3 के अनुरूप था, जिसमें एफ डी में सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत या उससे अधिक की वार्षिक कमी की परिकल्पना की गई है। बढ़े हुए लक्ष्य के लिए कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

3.6 सरकारी ऋण के लिए लक्ष्य

2018 में संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम ने एक नई धारा 2 (ए ए) पेश की, जिसने किसी भी तारीख में केंद्र सरकार के ऋण की अवधारणा को परिभाषित किया, जिसमें शामिल हैं:



इसके अलावा, संशोधित अधिनियम की धारा 2(बी बी) में "सामान्य सरकारी ऋण" की अवधारणा को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कुल ऋणों के योग के रूप में शामिल किया गया है, इसमें अंतर-सरकारी देनदारियां शामिल नहीं हैं।

ऋण संकेतकों के संबंध में निर्धारित राजकोषीय प्रबंधन लक्ष्य इस प्रकार थे:

- वित्तीय वर्ष 2024-25 तक केंद्र सरकार के ऋण को **सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए**
- वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सामान्य सरकारी ऋण को **सकल घरेलू उत्पाद का 60 प्रतिशत** करने के लिए

हालांकि, नियम मध्यवर्ती अवधि के दौरान प्राप्त किए जाने वाले किसी भी लक्ष्य के लिए प्रदान नहीं करते हैं।

3.6.1 केंद्र सरकार के ऋण

यू जी एफ ए से निकाले गए केंद्र सरकार के ऋण की स्थिति आकृति 3.11 में दी गई है।

आकृति 3.11: वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में केंद्र सरकार के ऋण का विवरण

	वस्तु	यू जी एफ ए के अनुसार (₹ करोड़ में)
क	संघ सरकार का आंतरिक ऋण	80,20,490
ख	बाह्य ऋण (वर्तमान दर पर)	5,44,394
ग	सार्वजनिक खाता देयताएं	18,78,733
घ	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ईबीआर	1,11,870*
ङ	कम: भारत सरकार का निवल नकद शेष	55,573
च	कुल केंद्र सरकार ऋण (क+ख+ग+घ+ङ)	1,04,99,914
छ	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल केंद्र सरकार ऋण	52.30%

*यू जी एफ ए में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए व्यय प्रोफाइल के विवरण 27 से प्राप्त किया गया है।

एफ आर बी एम अधिनियम की उपलब्धि ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत के लक्ष्य को 52.30 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से हासिल करने का लक्ष्य रखा है, केवल सकल घरेलू उत्पाद में बेहतर वृद्धि के साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है।

3.6.2 सामान्य सरकारी ऋण

एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 2, जैसा कि 2018 में संशोधित किया गया है, सामान्य सरकारी ऋण को अंतर-सरकारी देनदारियों को छोड़कर, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कुल ऋण के रूप में परिभाषित करता है। इसके अलावा, एफ आर बी एम अधिनियम की धारा 4 वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के साथ प्रतिशत से अधिक नहीं होने का प्रावधान करती है। यद्यपि यह अवधि-अंत लक्ष्य अधिनियम में प्रदान किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार के ऋण के रूप में, सामान्य सरकारी ऋण के मामले में भी एफ आर बी एम नियमों के तहत वार्षिक कमी लक्ष्य निर्धारित करने वाली अपेक्षित योजना तैयार नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त एफ आर बी एम अधिनियम की परिभाषा के अनुसार सामान्य सरकारी ऋण की गणना उपलब्ध नहीं थी।

सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में सामान्य सरकारी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 68.6 प्रतिशत था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सामान्य सरकार की समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विवरण शामिल है, प्रगति पर था।

3.7 सुझाव

सिफारिश 3क : सरकार को अनुमानों की प्रक्रिया की समीक्षा करने की जरूरत है। इसके अलावा, चूंकि मध्य-वर्ष के बेंचमार्क, खर्चों को नियंत्रित करने के लिए चेकपॉइंट के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए 30 सितंबर को समाप्त छमाही तक निर्धारित सीमा के भीतर खर्चों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

सिफारिश 3ख : वित्त मंत्रालय यू जी एफ ए से परिकलित और बी ए जी में उल्लिखित एफ डी आंकड़ों के बीच अंतर का समाधान कर सकता है।

सिफारिश 3ग : केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक केंद्र सरकार के ऋण और सामान्य सरकारी ऋण के लिए एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सकती है।